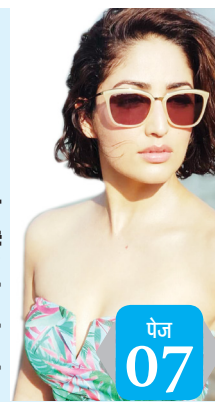


यूटर्न टाइम्स

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON    @UTURNTIMENEWS

राम गोपाल वर्मा की
तारीफ पर गदगद हुई
यामी गौतम
कहा- सफर ही सबसे बड़ा
शिक्षक रहा

पेज
07

VOL: 03 | ISSUE 180 | THURSDAY DATE 23-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER

Visit at : www.uturntime.com

कौन से दबे राज छिपा रहे हैं शिक्षा मंत्री, आखिर किस दबाव में उन्हें नहीं हटा पा रही सरकार: अखिलेश यादव

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने



बुधवार को लोकसभा में काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही है, जिस तरह से छात्रों के साथ किया जा रहा है वह देश के लिए सही नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सोचना चाहिए कि सरकार अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही है। सरकार पर किसी तरह का दबाव हो सकता है और सवाल किया कि क्या मंत्री के पास सरकार से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं, जिनकी वजह से उन्हें हटाना नहीं जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार डरी हुई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों ने साहस दिखाकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन जिस तरह पुलिस ने उनके साथ कार्रवाई की, वह चिंताजनक है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन का हुआ राजनीतिकरण, विपक्ष ने छात्रों का किया इस्तेमाल : बांसुरी स्वराज

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई

भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने बुधवार का भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांग्रेस में जंतर-मंतर पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन और नीट पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर बात की। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश बताया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं, जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निमार्ता मानते हैं। युवाओं के नेतृत्व में विकास का मूलमंत्र उन्होंने विकसित



भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण।

प्रधानमंत्री और मोदी सरकार विद्यार्थियों के हितों सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। सांसद ने कहा, 'मैं यह साफ कर देना चाहती हूँ कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार छात्रों के हितों को प्राथमिकता देती है। जब 11 मई को यह पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो मोदी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। शिक्षा मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज कराई और जांच सीबीआई को सौंप दी। 13 आरोपी अभी भी जेल में हैं।' बांसुरी स्वराज ने कहा कि नीट की पुनरीक्षा

महज 37 दिनों में संपन्न हुई और परिणाम मात्र 25 दिनों में घोषित कर दिए गए। कमियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया गया। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में 58 प्रतिशत महिलाएं हैं। मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से ये भी प्रार्थना की है कि इसका ट्रायल दैनिक के आधार पर पर हो और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, ताकि छात्रों को न्याय मिल पाए। सांसद ने कहा कि यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है।

संक्षिप्त

ताजा खबरें



खराब मौसम के कारण

अमरनाथ यात्रा लगातार

चौथे दिन भी स्थगित रही

श्रीनगर, यूटर्न/ 22 जुलाई । खराब मौसम के कारण बुधवार को लगातार चौथे दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और बालटाल तथा नुनवान (पहलगाम) के ट्रांजिट कैंपों और बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा लगातार चौथे दिन भी बंद रही। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शनिवार शाम को जम्मू-कश्मीर में सभी यात्राएं रोक दी थीं।

जंतर-मंतर घटना: दोषी पुलिस

अधिकारियों को नौकरी से

निकाले सरकार : आप

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । आम आदमी पार्टी (आप) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ कथित अभद्रता और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मामले में केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि महिलाओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता करने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल नौकरी से निकाला जाने की बुधवार को मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों की पहचान हो जाने के बावजूद अब तक न तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है। उन्होंने ह्याक्सह्व पर जारी बयान में कहा कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

लोगों को तेज एवं पारदर्शी तरीके के सेवाएं मुहैया कराना लक्ष्य: रेखा गुप्ता

सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की 84 सेवाओं का घटाया समय, कुछ सेवाएं जोड़ने की तैयारी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मिल रही 84 की समय सीमा कम कर दी है। इसके साथ ही कुछ नई सेवाओं को भी जोड़ने की तैयारी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य लोगों और कारोबारियों को तेज और पारदर्शी व्यवस्था में सेवाएं मुहैया कराना है।

इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने डिरेगुलेशन एक्सरसाइज फेज- 2 के तहत प्राथमिकता क्षेत्र-21 पर विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मिलने वाली सेवाओं में आवेदन से लेकर काम होने तक कितना समय लगता है और इसे किस तरह कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया अध्ययन बैठक में 18 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां नागरिक और व्यावसाय विभिन्न



लाइसेंस, परमिट, अनुमोदन और क्लीयरेंस के लिए एक जगह ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन के बाद व्यवस्था में सुधार करते हुए 84 सेवाओं में आवेदन के निस्तारण का समय कम कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ सेवाएं अब तत्काल मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने,

सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाना, तथा नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रणाली के माध्यम से लोगों तक तेज, आसान और नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है।



दिल्ली मेट्रो ने 16 स्टेशनों को बंद किया; राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । सुरक्षा कारणों से बुधवार को दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्याक्सह्व पर बताया कि अगले आदेश तक लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारारखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इससे पहले रविवार को भी सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद किया गया था।

राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, संसद की मर्यादाओं को किया जा रहा है तार-तार

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सदन में किया जा रहा व्यवहार बेहद गैरजिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद नीट परीक्षा व पेपर लीक के मुद्दे पर तुरंत चर्चा व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा और कथित प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।

सदन में निष्पक्ष चर्चा तभी संभव है जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें: खड़गे

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । विपक्ष ने बुधवार को संसद में स्पष्ट तौर पर कहा कि है सदन में निष्पक्ष चर्चा तभी संभव है जब कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। राज्यसभा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां निष्पक्ष व सार्थक चर्चा तभी हो सकती है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री का राजीनामा लेना चाहिए। खड़गे, सरकार द्वारा सदन में नीट संबंधी विषय पर चर्चा कराए जाने की बात का जवाब दे रहे थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा और उससे जुड़े विवादों पर तुरंत चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी व विपक्ष के अन्य सांसद नियम 267 के तहत सदन में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

ट्रेंडिंग न्यूज

प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने को लेकर देश से माफी मांगे कांग्रेस: मल्होत्रा

दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन की घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है और देश से माफी मांगने की मांग की है। श्री मल्होत्रा ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस द्वारा कल श्री मोदी के सरकारी आवास पर किया गया प्रदर्शन अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान और उल्लंघन है।



राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा प्रणाली गंभीर संकट से गुजर रही है और छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का आखिर कसूर क्या है। उनके अनुसार, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं और केवल एक निष्पक्ष एवं भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने के लिए तैयार, सरकार के सामने रखी शर्तें

» નઈ દિલ્લી, યૂટર્ન/ 22 જુલાઈ ।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही और छात्रों के हितों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने केन्द्र सरकार से आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट लिखित आश्वासन मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा आश्वासन मिलने पर ही वह अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे।

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्याक्सहू पर एक खुला पत्र साझा किया, जिसे उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी. नड्डा और

आयुष्मान भारत लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बदल रहा है: उपराष्ट्रपति

» નઈ દિલ્લી, યૂટર્ન/ 22 જુલાઈ ।

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को कुशल, करुणामय और सेवाभावी कार्यबल के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के दो स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में देश की यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और समर्पित स्वास्थ्य पेशेवरों को तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। कोयंबटूर में जीकेएनएम ग्रुप कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस संस्थान को जीकेएनएम ग्रुप द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक सेवा की लंबी परंपरा में एक और मील का पत्थर बताया। उन्होंने जी. कुपुस्वामी नायडू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिछले कई दशकों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि 1952 में स्थापित इसका 50 बिस्तारों वाला अस्पताल आज 750 बिस्तारों वाले बहु-विशेषज्ञता संस्थान में विकसित हो गया है और साथ ही साथ स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक अपने शैक्षिक प्रयासों का विस्तार कर रहा है। नर्सिंग पेशे के महत्व पर जोर देते हुए सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नर्स केवल देखभाल करने वाली नहीं होतीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर होती हैं। उन्होंने कहा कि वे मरीजों को सुरक्षित, संरक्षित और देखभाल का एहसास कराती हैं। दवाओं के साथ-साथ उनकी करुणा और चिंता उपचार में अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। उन्होंने इस पेशे में आने वाले छात्रों से आग्रह किया कि वे आत्मविश्वास, करुणा, समर्पण और साहस के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और हमेशा अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखें।

केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नाम संबोधित किया गया है। उन्होंने पत्र में बताया कि दोनों मंत्री मंगलवार रात अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। वांगचुक ने लिखा कि मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इनमें परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संसद में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने जैसी मांगें शामिल हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चर्चा के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किए जाने की बात सामने

कांवड़ यात्रा 2026: एडीजी अग्निशमन ने तैयारी की समीक्षा की, शिविरों एवं बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के कड़े निर्देश

» गाजियाबाद, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक (अग्निशमन एवं आपात सेवा) पद्मजा चौहान ने गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली पहुंचकर कांवड़ यात्रा से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं और अमरोहा सहित विभिन्न जनपदों के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एडीजी पद्मजा चौहान ने सभी अधिकारियों से कांवड़ यात्रा मार्गों पर की जा रही अग्नि सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले कांवड़ शिविरों में अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिविर

जंतर-मंतर घटना: दोषी पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाले सरकार : आप

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

आम आदमी पार्टी (आप) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ कथित अभद्रता और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मामले में केन्द्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि महिलाओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता करने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल नौकरी से निकाला जाने की बुधवार को मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों की पहचान हो जाने के



आई। अपने पत्र में वांगचुक ने 20 जुलाई को आयोजित हचलो संसदद्वि मार्च का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की कथित सख्ती और बल प्रयोग के बावजूद यह मार्च पूरी तरह



संचालकों और आयोजकों को आग से बचाव, गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग, विद्युत उपकरणों के संचालन और आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों की पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान किसी भी संभावित अग्निकांड या आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें पूरी तरह सतर्क रहें और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके

शातिपूर्ण रहा। देश और दुनिया ने देखा कि युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी और संयम का परिचय दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वांगचुक ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रियों की मुलाकात के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने की अपील की है। कुछ सांसद व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने भी पहुंचे हैं, जबकि अन्य के मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों ने उन्हें याद दिलाया कि देश और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अभी बाकी



**राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण
दिवस पर देसी घी की मिठाई
खिलाकर मनाया गया उत्सव**



अलावा सभी जिलों में आपसी समन्वय बनाकर त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर फायर स्टेशन वैशाली में अग्निशमन कर्मियों के शारीरिक प्रशिक्षण और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित व्यायामशाला (जिम) का भी लोकार्पण किया गया। वहीं, कविनगर स्वदेशी कपाउंड इंडस्ट्री द्वारा अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराया गया एक वाटर बाउजर भी एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर विभाग को समर्पित किया।

महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियो में डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों की पहचान की जा सकती है और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस मामले में जवाब देने की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ गंभीर बदसलुकी की गयी, युवाओं के साथ

मारपीट की गयी और पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में मौजूद लोगों ने कीलों लगे डंडों से प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। इस पूरे घटनाक्रम पर केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आप नेता ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार वास्तव में युवाओं की बात सुनना चाहती है, तो उसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो इससे यह संदेश जायेगा कि पुलिस की कथित बर्बरता को शीर्ष स्तर पर संरक्षण प्राप्त है।



**प्रेरणा वृद्धाश्रम में सात समुद्र पार बर्लिन से
बुर्जुगोंका आशीर्वाद लेने पहुंची दिव्या सैनी**

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 22 जुलाई । धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम की ख्याति विदेश में भी हो रही है। इसी लिए दूसरे देशों से नियमित लोग आते रहते हैं। इसी क्रम में सात समुद्र पार बर्लिन से प्रेरणा वृद्धाश्रम में दिव्या सैनी बुर्जुगोंसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं संचालक डा. जय भगवान सिंगला ने बताया कि प्रेरणा वृद्धाश्रम की ख्याति सुनकर बुर्जुगोंसे आशीर्वाद लेने के लिए दिव्या सैनी नाम की यह लड़की जर्मनी से प्रेरणा वृद्धाश्रम में पहुंची। यह लड़की बुर्जुगोंसे मिलकर और उनके दुःख दर्द जानकर भावुक हो गई। उसने कहा कि हमारा देश तो समृद्ध परंपराओं, संस्कार और उच्च संस्कृति से ओतप्रोत देश है, फिर हमारे देश में ऐसे संस्कार कहां से आ गए। विदेश की बात तो अलग है वहां तो कोई किसी से लगाव नहीं रखता।

प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण

» **अश्विनी वालिया**

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 22 जुलाई । श्रीमद् भगवद गीता प्राथमिक विद्यालय बालघर में नन्हे बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भवन निर्माण के लिए विद्यालय द्वारा स्वयं खरीदकर आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिल रही है और समय की बचत हो रही है। प्रबंधन कमटी के जीवन मौदगिल ने बताया कि निर्माण स्थल पर मशीनों की सहायता से नींव, दीवारों तथा अन्य निर्माण कार्यों को व्यवस्थित और तेजी से पूरा किया जा रहा है।



योजना के अनुसार प्रगति पर है। आधुनिक तकनीक और मशीनों के प्रयोग से भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि नया भवन बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण, पर्याप्त कक्षाओं और

आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। प्रबंधन समिति के अथक प्रयासों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक मजबूत विद्यालय भवन बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

सरकार को कॉकरोच तब दिखे जब वे संसद तक पहुँच गए



संदीप शर्मा

सरकारें हाथी, शेर वगैरह को पहचानने में माहिर होती हैं ये दोनों बड़े खतरे का प्रतीक हैं। उनके पास खुफिया एजेंसियां, ड्रोन, बैरिकेड, वॉटर कैनन और हमलावर सेना को रोकने के लिए काफी पुलिस बल होता है। लेकिन वे कॉकरोच पर ध्यान देने में उतनी माहिर नहीं होतीं। कॉकरोच जनता पार्टी जिसका नाम किसी राजनीतिक संगठन के बजाय कॉलेज के मजाक जैसा लगता था झू को सोशल मीडिया की एक और अजीब चीज मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। जाहिर है, कोई गंभीर आंदोलन खुद को कॉकरोच नहीं कहेगा। सत्ता में बैठे लोगों ने मजाक उड़ाया। आखिरकार, लोकतंत्र में कीड़े-मकोड़ों की वजह से किसी की नींद नहीं उड़ती। लेकिन फिर उन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। सरकार को राजनीतिक कीट-विज्ञान का पहला नियम पता चला: कॉकरोच कभी अकेले नहीं आता। वह अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और कुचलने की हर कोशिश के बावजूद जिंदा रहने की अद्भुत क्षमता के साथ आता है। जब तक दिल्ली ने बैरिकेड लगाए, तब तक यह आंदोलन लोगों की सोच में उन बैरिकेड्स को पार कर चुका था। एक और सबक है। सत्ता अक्सर मजाक को गैर-जरूरी समझ लेती है। राजनीति का इतिहास ऐसे आंदोलनों से भरा पड़ा है जो मजाक के तौर पर शुरू हुए और बाद में सिरदर्द बन गए। हर सत्ता को लगता है कि वह तय कर सकती है कि किस विरोध पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जनता की सोच अक्सर अलग होती है। विडंबना मजेदार है। जो सरकार अपनी तकनीकी क्षमता, डेटा एनालिटिक्स और निगरानी पर गर्व करती है, उसने शासन के सबसे पुराने सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया: जिन शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है, वे शायद ही कभी गायब होती हैं। वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। CJP सफल होती है या खत्म हो जाती है, यह बात लगभग गौण है। उसने पहले ही कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हासिल कर लिया है। उसने सरकार को एक ऐसे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया है जिसे उसने कभी जवाब देने लायक भी नहीं समझा था। शायद राजनीति में सबसे महंगी गलती विरोधी को बहुत ज्यादा आंकना नहीं है। बल्कि उसका मजाक उड़ाना है। सरकारों के लिए, असली मुसीबत शायद ही कभी कॉकरोच होती है। असली मुसीबत होती है आत्म-संतुष्टि।

बैरिकेडों के साये में लोकतंत्र किसान, व्यापार समझौता और भरोसे का संकट

कुमार कृष्णन



इस बार का आंदोलन केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या कर्जमाफी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौता है। किसान संगठनों की आशंका है कि यदि कृषि और डेयरी क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा दिए बिना यह समझौता लागू हुआ, तो सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में प्रवेश करेंगे। इससे सबसे बड़ा आघात उन छोटे और सीमांत किसानों को लगेगा, जो पहले ही बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।

लो

कतंत्र की पहचान केवल चुनावों से नहीं होती; उसकी असली शक्ति संवाद में निहित होती है। चुनाव सत्ता तय करते हैं, लेकिन संवाद समाज को जोड़ता है। जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने वाले नागरिकों का सामना बातचीत से पहले बैरिकेड, कंक्रीट की दीवारों, पुलिस बंदोबस्त और हिरासत से होने लगे, तब प्रश्न केवल कानून-व्यवस्था का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र की प्रकृति पर खड़ा हो जाता है।

दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर वही दृश्य दिखाई दिया, जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति का स्थायी प्रतीक बन गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राजधानी की ओर बढ़े। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि खेती, बाजार और आजीविका को लेकर गहरी आशंकाएं थीं। लेकिन शंभू बॉर्डर पर उनका स्वागत संवाद से पहले सीमेंट के ब्लॉकों, लोहे के बैरिकेडों और भारी पुलिस बल से हुआ।

इस बार घटनाक्रम केवल प्रतीकात्मक नहीं था। देश बचाओ मोर्चा के आ'न पर पंजाब के विभिन्न जिलों से हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने निकले। फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, मानसा और बठिंडा से किसानों के जत्थे शंभू सीमा तक पहुंचे, लेकिन हरियाणा सरकार ने सीमा को लगभग अभेद्य बना दिया। घग्गर नदी के पुलों पर भी कंक्रीट के अवरोध रख दिए गए। कई किसानों को अपने वाहन छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ा।

किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राजधानी में अपनी बात रखने से रोक रही है। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस का कहना है कि राजधानी की



सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। कई किसान नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। यहीं से यह घटनाक्रम केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह जाता। सवाल यह है कि किसी लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर संवाद होना चाहिए या बैरिकेड?

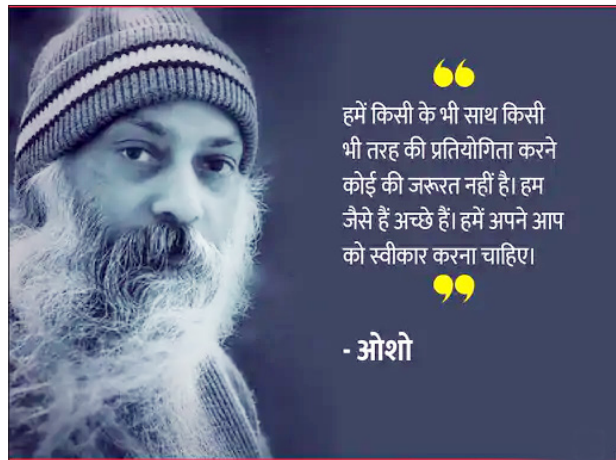
सरकार का कहना है कि ये कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं, जबकि किसान संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को सीमित किया जा रहा है। दोनों दावों के बीच भारतीय लोकतंत्र एक कठिन प्रश्न से जूझ रहा है—क्या असहमति अब प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है?

इस बार का आंदोलन केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या कर्जमाफी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौता है। किसान संगठनों की आशंका है कि यदि कृषि और डेयरी क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा दिए बिना यह समझौता लागू हुआ, तो सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में प्रवेश करेंगे। इससे सबसे बड़ा आघात उन छोटे और सीमांत किसानों को लगेगा, जो पहले ही बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। भारत की कृषि को केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। देश के अधिकांश किसान दो-तीन एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। दूसरी ओर

अमेरिका की कृषि विशाल व्यावसायिक फार्मों, उन्नत तकनीक और व्यापक सरकारी सहायता पर आधारित है। ऐसी असमान परिस्थितियों में खुली प्रतिस्पर्धा को लेकर किसानों की चिंता स्वाभाविक है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी है। वैश्विक व्यापार समझौते अवसर भी पैदा करते हैं। नए बाजार, कृषि निर्यात और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के विस्तार से किसानों को लाभ भी मिल सकता है। इसलिए मूल प्रश्न व्यापार समझौते का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि उसकी शर्तों की पारदर्शिता और कृषि हितों की सुरक्षा है।

यहीं सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। यदि किसानों की आशंकाएं निराधार हैं तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कौन-से प्रावधान प्रस्तावित हैं। यदि कुछ जोखिम हैं तो उनके समाधान भी सार्वजनिक होने चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास गोपनीयता से नहीं, पारदर्शिता से बनता है।

बीते वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है। किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन पर सबसे पहले धारा 144 लागू होती है, फिर बैरिकेड लगते हैं, नेताओं को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद संवाद की बात होती है। लोकतंत्र का स्वाभाविक क्रम इसका उलटा होना चाहिए। पहले बातचीत, फिर समाधान का प्रयास और अंत में आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक उपाय। शंभू बॉर्डर अब केवल पंजाब और हरियाणा की सीमा नहीं रह गया है।



हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने कोई की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए।

- ओशो

सीखचों में सिसक रही हैं अपने सुहाग का खून करने वाली विवाहिताएं



मनोज कुमार अग्रवाल

देश की बहुत सारी जेलों में अंधी वासना अवैध संबंध के चलते अपना सुहाग को उजाड़ने वाली कुलटाएं अपने कृत्यों के लिए दिनरात त्रासदी भुगत रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला जेल में ही पिछले कुछ महीनों में सामने

आए अवैध रिश्तों के ताने बाने में फंसकर अपने ही हाथों से अपने सुहाग को कल्ल कर जीवन को नरक में धकेलने की की कहानी दबी पड़ी है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ चौधरी चरण सिंह जिला कारागार की बैरक नंबर 12ए में छह महिलाएं भी बंद हैं, जिन्होंने पराए संबंधों के मोह में अपने ही परिवार के खिलाफ घातक षड्यंत्र रच डाला। पांच जहां पति की हत्या की गुनहगार हैं, छठी ने अपनी कोख से जन्मे बेटे को ही मरवा दिया। यूपी की सबसे पुरानी जेलों में शुमार मेरठ की जिला जेल में फिलहाल 67 महिला बंदी हैं, जिन्हें बैरक 12ए और 12बी में रखा गया है। पति को सांप से डसवाकर मरवाने वाली दामिनी को भी इसी बैरक में मुस्कान, अंजलि, रविता, कोमल और गुरुप्रीत के साथ रखा गया है। जेल प्रशासन के अनुसार दामिनी फिलहाल किसी से बातचीत नहीं कर रही है। उसकी काउंसलिंग की तैयारी है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा बताते हैं कि इन महिलाओं को एक ही बैरक में रखने का



उद्देश्य यह है कि वे एक-दूसरे का सहारा बन सकें। अधिकांश को अपने किए पर पछतावा है इन सबके भीतर जेल से बाहर आने की छटपटाहट है लेकिन भविष्य खत्म हो जाने का अहसास भी है।

इन पति हंता महिलाओं से जब परिवार वाले बच्चों के साथ मिलने आते हैं तो उनका भावनात्मक संतुलन टूट जाता है। ऐसे समय में वे एक-दूसरे से कहती भी हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो

गई थी, जो खुद ही अपनी गृहस्थी उजाड़ ली। सुबह सुंदरकांड के पाठ के बाद मुस्कान अपनी बेटी के साथ समय बिताती है, जबकि अंजलि, गुरुप्रीत, रविता और कोमल सिलाई-कढ़ाई में खुद को व्यस्त रखती हैं।

आपको बता दें मुस्कान रस्तोगी का नीला ड्रम कांड हो अथवा रविता और दामिनी..। सभी ने पति के रहते भी दूसरे युवकों से आशिकी का चक्कर चलाया प्यार के चक्कर में अपने पति का काम तमाम कर अपराध की अंधी राह पर जाकर खून से अपने हाथ रंग लिए। संगीता, अंजलि, कोमल और कविता की भी यही कहानी है। पति से भावनात्मक और जिस्मानी पूर्ति के बावजूद वे दूसरे आशिकों के साथ रंगरलियां मनाने की वासना भरी चाहत में ऐसी भटकी कि कुछ महिलाओं ने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया तो एक ने बेटे को ही मार दिया। जिन सपनों के लिए उन्होंने यह खतरनाक रास्ता अख्तियार किया, वे टूट चुके हैं। जेल में कोई सिलाई-कढ़ाई सीख रही तो कोई बच्चों को पढ़ा

रही है हर सुबह जेल में बजने वाले सुंदरकांड को सुन कर मन की शांति पाने की कोशिश करती है। जाने-अनजाने उन्होंने यह कदम उठा तो लिया लेकिन सलाखों के पीछे अब सिर्फ दर्द है, पछतावा है और बेबस सिसकियां भी।

आपको पता होगा तीन मार्च 2025 की रात को ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। ड्रम के अंदर सीमेंट से शव को जमा दिया था। मुस्कान और साहिल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों के मुकदमे में जल्द ही निर्णय भी आने वाला है।

परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर निवासी 28 वर्षीय राहुल से अंजलि के तीन बेटे हैं। इसके बावजूद अंजलि का दिल पड़ोसी अजय पर आ गया। राहुल खेती बाड़ी व पशुपालन करता था, जबकि अजय आवारा किस्म का था और मौजमस्ती करता था। अजय ही अंजलि को रास्ते में से पिकअप कर लेकर होटल पहुंच जाता था। राहुल इसका विरोध करता था।

डॉलर जुटाने के लिए सरकार की महामुहिम, बैंकों को मिले टारगेट

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए शुरू की गई रियायती स्वैप योजना ने शानदार शुरूआत की है। 17 जुलाई तक इस योजना के तहत 20.72 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, जिसमें विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीय (बैंक) जमा यानी (एफसीएनआर-बी) का बड़ा योगदान है। इस गति को बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने अब बैंकों के लिए 30 सितंबर तक एफसीएनआर-बी जमा जुटाने के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, जो इस योजना की अंतिम तिथि भी है। सरकार का लक्ष्य विभिन्न उपायों से कुल 90 अरब डॉलर जुटाना है, जिसे पूरा करने के लिए बैंकों पर दबाव बढ़ गया है।

लावा अपनी विराट वी 1 सीरीज को भारत में जल्द करेगी लांच

दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । स्मार्टफोन निमाता कंपनी लावा अपनी बहुप्रतीक्षित विराट वी 1 सीरीज को जल्द लॉन्च करने जा रही है। ग्राहकों को इस सीरीज में कम बजट में शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। इस सीरीज में लावा विराट वी1 5जी और लावा विराट वी1 4जीमॉडल शामिल होंगे, जिन्हें कम बजट में शानदार फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा।

लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि कर दी है, जिनमें 120एचझेड डिस्प्ले, एआई कैमरा, आईपी64 रेटिंग और दमदार बैटरी शामिल हैं। ये स्मार्टफोन विशेष रूप से फिलपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जो 120एचझेड रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव बेहद स्मूथ रहेगा। धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षा के लिए इनमें आईपी64 रेटिंग दी गई है। सिक्वोरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलेगा। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए दोनों फोन में 13एमपी का एआई डुअल रियर कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कंपनी ने वर्चुअल रैम फीचर भी शामिल किया है, जो जरूरत पड़ने पर फोन की रैम को बढ़ाने में मदद करेगा। लावा विराट वी1 5जी में यूनिसेक टी8200 प्रोसेसर, 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी सबसे बड़ी खासियत 6000 एमएएच की विशाल बैटरी होगी जो लंबे समय तक साथ निभाने का दावा करती है।

पोको कंपनी पोको एम 8 पावर और पोको एक्स 8 जल्द आएगा बाजार में

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । पोको कंपनी दो नए मॉडल, पोको एम 8 पावर और पोको एक्स 8 लॉन्च करने की तैयारी में है। ये दोनों स्मार्टफोन रेडमी नोट 17 और रेडमी नोट 17 प्रो के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, जिसका अर्थ है कि इनमें समान आंतरिक स्पेसिफिकेशन्स होंगे, लेकिन बाहरी डिजाइन और ब्रांडिंग पोको के तहत होगी। जानकारी के मुताबिक, पोको इन दोनों स्मार्टफोन को इसी तिमाही (क्वार्टर) में भारत में लॉन्च कर सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इनकी कीमतें चीन के रेडमी मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी अधिक हो सकती हैं। पोको एक्स 8 में पीछे की तरफ 50एमपी का मुख्य कैमरा और 2एमपी का डेथ सेंसर मिल सकता है।

फार्मा शेयरों में बड़ी गिरावट, जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप ने 200 प्रतिशत तक के टैरिफ का किया ऐलान

» **मुंबई, यूटर्न/ 22 जुलाई ।**

फार्मा शेयरों में बुधवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को माना जा रहा है, जिसके तहत अगस्त 2028 से सभी जेनेरिक दवाओं पर 100 प्रतिशत और अगस्त 2029 से 200 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

इससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का फार्मा कंपनियों का मुख्य सूचकांक निफ्टी फार्मा 2 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया।

सुबह 10:30 बजे तक, ग्लैंड फार्मा (4.62 प्रतिशत), पीरामल फार्मा (3.92 प्रतिशत), ल्यूपिन (3.81 प्रतिशत), जेबी



केमिकल्स (3.87 प्रतिशत), अजंता फार्मा (3.03 प्रतिशत), सिप्ला (1.87 प्रतिशत), मैनकाइंड फार्मा (1.69 प्रतिशत), डॉ.रेड्डी

ई20 पेट्रोल से पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा घट सकता है, लेकिन इंजन को नुकसान का कोई सबूत नहीं: सरकार

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई ।**

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के इस्तेमाल से ई10 पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) में मामूली कमी आ सकती है। हालांकि, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहनों में खराबी आने का कोई सत्यापित (वेरिफाइड) प्रमाण नहीं मिला है।

राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि ई10 के लिए डिजाइन किए गए पुराने वाहनों में माइलेज में होने वाली कमी आमतौर पर करीब 3 से 5 प्रतिशत तक ही सीमित रहती है।

उन्होंने कहा कि किसी वाहन का माइलेज केवल पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग की आदत, वाहन का रखरखाव, टायर प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट और एयर कंडीशनर (एसी) के उपयोग जैसे कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।

सुरेश गोपी ने कहा, 'ई10 के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में होने



वाली कमी सामान्यतः मामूली (करीब 3-5 प्रतिशत) होती है।'

उन्होंने आगे कहा, 'कुछ पुराने वाहनों में माइलेज में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन ई20 पेट्रोल के कई फायदे भी हैं। इसमें अधिक ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक प्रदर्शन, बेहतर दहन क्षमता और अधिक स्मूथ एक्सिलरेशन मिलता है।'

इस बीच, इसी महीने 7 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर आलोचकों को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

लैब्स (1.49 प्रतिशत), सन फार्मा (1.00 प्रतिशत) और बायोकॉन (1.01 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले दो वर्षों तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद एक वर्ष के लिए टैरिफ 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उसके बाद इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को अमेरिका में वापस लाना है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अमेरिका में अपने उत्पादन संयंत्र और उपकरण स्थापित

करने का अवसर दिया जाएगा। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें बढ़े हुए टैरिफ के रूप में दंड का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पेटेंट, ब्रांडेड और इनोवेटिव दवाओं पर मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और यह पहले की तरह लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना और देश में दवा निर्माण को बढ़ावा देना है।

भारतीय शेयर बाजार में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 658 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,811 और निफ्टी 182 अंक या 0.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,002 पर था।

लगातार तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 715 अंक फिसला

» **मुंबई, यूटर्न/ 22 जुलाई ।**

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के चलते हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को लगातार तीसरे सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस बीच घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 715.06 प्रतिशत या 0.92 प्रतिशत गिरकर 76,755.05 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 50 191.45 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 23,996.25 पर आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिगो, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंप्रोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, मैक्स हेल्थ और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो वहीं, बजाज-ऑटो, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर और इटरनल के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए।

आसुस का नया आसुस पीएडी भारत में लांच

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई ।**

भारतीय बाजार में आसुस कंपनी ने फिर टैबलेट सेगमेंट में वापसी करते हुए नया आसुस पीएडी लॉन्च किया है। कंपनी ने फिलहाल इस टैबलेट की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आसुस पीएडी की बिक्री 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फिलपकार्ट, आसुस ई-शॉप, आसुस और आरओजी स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल और कंपनी के अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह टैबलेट छात्रों, पेशेवरों और मनोरंजन पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें एक बड़ी ओलेड स्क्रीन, शक्तिशाली प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

आसुस पीएडी में 12.2 इंच का 2.8 के ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144एचझेड है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी कंटेंट आसानी से देखा जा सकता है। टीयूवी सर्टिफिकेशन के साथ, कंपनी का दावा है कि



यह डिस्प्ले आंखों पर कम दबाव डालता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रैम और 128जीबी या 256जीबी स्टोरेज विकल्पों के साथ आता है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले चार स्पीकर दिए गए हैं, जबकि कनेक्टिविटी के लिए वायफाय 6ई, ब्ल्यूटूथ 5.3 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं।

ऐपल की मैकबुक और आईपैड पर मुफ्त एक्सेसरीज का ऑफर

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई ।**

भारत में ऐपल ने अपनी बहुप्रतीक्षित बैक टू स्कूल सेल 2026 शुरू कर दी है। कंपनी इस सेल में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए शानदार डीलस और मुफ्त उपहार लेकर आई है। इस सेल में मैकबुक, आईपैड और मैकबुक नियो जैसे ऐपल उत्पादों पर एजुकेशन डिस्काउंट के साथ



मुफ्त एयरपॉड्स, ऐपल पेंसिल प्रो और एयरटैग्स जैसे आकर्षक उपहार मिल रहे हैं। यह सेल 27 अगस्त तक चलेगी। यह उन सभी के लिए एक शानदार अवसर है जो नया ऐपल डिवाइस खरीदने की योजना बना रहे हैं।

इस ऑफर का लाभ केवल कॉलेज के छात्र ही नहीं, बल्कि स्कूल या कॉलेज के शिक्षक, स्टाफ और अपने बच्चों के लिए ऐपल डिवाइस खरीदने वाले माता-पिता भी

एजुकेशन स्टोर के माध्यम से उठा सकते हैं। अगर आप नया मैकबुक एयर एम5 खरीदते हैं, जिसकी शुरूआती कीमत रूपए 1,37,900 है, तो आपको मुफ्त एयरपॉड्स 4 या 4 एयरटैग्स का पैक चुनने का विकल्प मिलेगा। ग्राहक थोड़ी अतिरिक्त राशि देकर एयरपॉड्स 4 को सिर्फ रूपए 5,000 में या एयरपॉड्स प्रो 3 को सिर्फ रूपए 13,000 में अपग्रेड भी कर सकते हैं।

नई दिल्ली, यूटर्न/ 22 जुलाई । काँकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच में दिल्ली पुलिस ने एक नया मोड़ लिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के कुछ कथित चैट संदेशों और एक सीक्रेट एप के इस्तेमाल की पड़ताल कर रही है। यह जांच उन संदेशों पर केंद्रित है, जिनमें संभावित इंटरनेट बंदी की स्थिति में संपर्क बनाए रखने की तैयारी और आंदोलन के लिए जान देने जैसी बातें कही गई हैं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन कथित चैट संदेशों की प्रामाणिकता और उनमें शामिल व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सामने आए संदेश वास्तविक हैं और किसी गलत सूचना या दुष्प्रचार का हिस्सा। एक वरिष्ठ पुलिस सूत्र ने बताया कि कुछ कथित संदेशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की स्थिति में संपर्क बनाए रखने और प्रदर्शन के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की गई है।

संक्षिप्त खबरें बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है ईरान-अमेरिका



» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 22 जुलाई

अमेरिका ने ईरान पर बातचीत को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में चल रही आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री रुबियो ने कहा, 'इस वक्त हमारी समस्या यह है कि वे बातचीत को लेकर गंभीर नहीं हैं। अगर वे गंभीर हैं, तो हम भी गंभीर हैं। अगर वे गंभीर नहीं हैं, तो हम अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे।' कतर, मिस्त्र, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान के समक्ष 10 दिनों के युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है। एक्सियोस की सोमवार रात की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और उसने इजरायल से ऐसे कदम उठाने से बचने का आग्रह किया है, जो कूटनीतिक रास्ते बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही बातचीत के विफल होने की आशंका के महेनजर अमेरिका तैयारियां भी कर रहा है।

पोलैंड ने हूती को सऊदी अरब के जहाजों पर समुद्री नाकाबंदी करने पर गंभीर चेतावनी दी

वारसॉ, यूटर्न/ 22 जुलाई । पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने यमन के हूती संगठन को चेतावनी दी है कि अगर वे सऊदी अरब के जहाजों पर समुद्री नाकेबंदी लागू करते हैं तो उन्हें 'गंभीर नतीजों' का सामना करना पड़ेगा। हूती सैन्य प्रवक्ता ने सोमवार को घोषणा की कि संगठन ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों की नाकेबंदी के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू की है। श्री सिकोरस्की ने मंगलवार को टीवीएन से कहा, 'अगर मैं हूती होता, तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें बहुत गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'हम ईरान से फंड पाने वाले कुछ गुरिल्लाओं के बंधक नहीं बन सकते।' सऊदी अरब वर्तमान में पोलैंड को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2025 में, पोलैंड ने लगभग 25.4 मिलियन टन तेल का आयात किया, जिसमें से 12.3 मिलियन टन सऊदी अरब से आया था।

25 जिलों में 7.27 लाख से अधिक लोग प्रभावित मुख्यमंत्री सरमा ने राहत शिविरों का किया दौरा

» गुवाहाटी, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को बताया कि इस वर्ष 29 अप्रैल से 21 जुलाई के बीच राज्य के 25 जिलों में आई बाढ़ से 7,27,506 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और प्रभावित लोगों की आजीविका बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाढ़ की ताजा स्थिति साझा करते हुए लिखा, 'असम बाढ़ से हुई व्यापक तबाही का यह वास्तविक स्वरूप है। मैंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि वे इस संकट में अकेले नहीं हैं। हमारी सरकार राहत, पुनर्वास और आजीविका के पुनर्निर्माण के हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।'



मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, बाढ़ से गोलपाड़ा, कछार, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, बिश्वनाथ, चराइदेव, नलबाड़ी, बजाली, चिरांग, कोकराझार, बोंगाईगांव, बक्सा, शिवसागर, दरांग, सोनितपुर, तिनसुकिया, उदलगुरी,

गोलाघाट, नगांव, कार्बी आंगलोंग, कामरूप, कामरूप महानगर और होजाई सहित 25 जिले प्रभावित हुए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ का असर 74 राजस्व सर्किलों और 1,700 गांवों पर पड़ा है। राज्य में फिलहाल 95 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं,

जहां 18,574 विस्थापित लोग रह रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों तक खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 469 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष बाढ़ के कारण अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक 14 मौतें शिवसागर जिले में हुईं। इसके अलावा चराइदेव में छह, जोरहाट में पांच, धेमाजी और गोलाघाट में दो-दो तथा सोनितपुर और कार्बी आंगलोंग में एक-एक व्यक्ति की जान गई। वहीं, 19 अप्रैल को कामरूप महानगर जिले में शहरी बाढ़ की एक घटना में भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल तीन लोग लापता हैं, जिनमें धेमाजी, चराइदेव और कार्बी आंगलोंग से एक-एक व्यक्ति शामिल है।

तिमोर-लेस्ते ने भारत को एलएनजी क्षेत्र में निवेश के लिए दिया न्योता

वॉशिंगटन, यूटर्न/ 22 जुलाई
दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तिमोर-लेस्ते ने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), तेल रिफाइनिंग और शिक्षा क्षेत्र में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया है। यह जानकारी देश के पूर्व विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने दी।

अमेरिका में तिमोर-लेस्ते के राजदूत जोस लुइस गुटेरेस ने आईएनएस को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि तिमोर-लेस्ते के पास तेल और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त संसाधन हैं और देश को एलएनजी संयंत्र, रिफाइनरियों और ग्रेटर सनराइज गैस क्षेत्र से जुड़ी पाइपलाइन के विकास के लिए निवेश की आवश्यकता है।

बिहार के कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन में मंत्री, लिसा नंदी की कुर्सी बरकरार

» लंदन, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने औपचारिक रूप से देश की कमान संभाल ली है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से नए राजनीतिक मॉडल की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री बर्नहैम ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। इस नए मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दो प्रमुख नेताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो ब्रिटेन की राजनीति में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मे कनिष्क नारायण को बर्नहैम सरकार में कैबिनेट स्तर का दर्जा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरपुर से 12 वर्ष



की आयु में यूके चले गए कनिष्क ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक और अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की। सिलिकॉन वैली और टेक सेक्टर में वर्षों के अनुभव के बाद, उन्होंने 2024 के चुनावों में लेबर पार्टी

के टिकट पर वेल ऑफ ग्लैमरगन सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे सरकार में जूनियर मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

दूसरी ओर, भारतीय मूल की वरिष्ठ सांसद लिसा नंदी को बर्नहैम कैबिनेट में संस्कृति सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। मैनचेस्टर में जन्मी लिसा नंदी का भारत के कोलकाता शहर से गहरा पारिवारिक संबंध है। राजनीति में आने से पूर्व सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों पर कार्य कर चुकीं लिसा 2010 में पहली बार विगन सीट से सांसद चुनी गई थीं। वे उस क्षेत्र से सांसद बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई नेता बनीं। ब्रिटेन की इस नई कैबिनेट में भारतीय मूल के इन दोनों कद्दावर नेताओं की मौजूदगी न केवल उनके राजनीतिक कद को बढ़ाती है।

कनाडा ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद का किया ऐलान

भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशों के बीच बड़ा कदम

» टोरंटो, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की पाकिस्तान यात्रा के समापन से ठीक पहले कनाडा ने इस्लामाबाद को 47 मिलियन डॉलर (करीब 4.7 करोड़ डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह धनराशि पाकिस्तान में विकास कार्यों और सुरक्षा पहलों पर खर्च की जाएगी। कनाडा का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वह भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।



जानकारी के अनुसार, इस पैकेज में से 2.2 मिलियन डॉलर से अधिक की नई फंडिंग सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसमें इंटरपोल, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के संयुक्त प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, कनाडा से जुड़े तीन विकास आधारित

प्रोजेक्ट्स के लिए 45 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की गई है। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए भारत के खिलाफ कनाडा से कूटनीतिक समर्थन की मांग भी की। भारत और कनाडा के रिश्तों में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान काफी कड़वाहट आ गई थी, जब सरे में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर अनर्गल आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाल ही में कनाडाई पुलिस प्रशासन (आरसीएमपी) ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच और दर्ज आरोपों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो भारतीय अधिकारियों की सलिपता की ओर इशारा करता हो, और भारत ने जांच में पूरा सहयोग दिया है।

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का यू-टर्न, बोले-नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं

» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 22 जुलाई ।

न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने कहा कि सिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कानूनी समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलने के बाद कि उनके प्रशासन के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अपने चुनावी वादे से पीछे हटते हुए यह बात कही। हालांकि, ममदानी ने नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी'



कहा और ट्रम्प प्रशासन से आग्रह किया कि वे सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आने पर उन्हें गिरफ्तार करें। ममदानी ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहां आते हैं तो क्या न्यूयॉर्क शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकता है।' उन्होंने कहा, 'यह स्पष्ट है कि हमारे पास इस वारंट को

लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है।' ममदानी ने कहा कि संघीय सरकार के पास ऐसा अधिकार है और उन्होंने वॉशिंगटन से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल होने और उसके वारंट को लागू करने का आ'न किया। अमेरिका इस कोर्ट का सदस्य नहीं है। मेयर की यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई कि नेतन्याहू को उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा। ट्रम्प ने सोमवार को ट्विटर सोशल पोस्ट में कहा, 'संयुक्त

राज्य अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।' अपने मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान, ममदानी ने बार-बार कहा था कि जब इजराइली नेता न्यूयॉर्क आएंगे तो वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश देंगे।

उन्होंने हाल ही में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन' को बताया था कि उनका प्रशासन वारंट को लागू करने के बारे में शहर के कानून विभाग के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा था।